

DHARIWALCORP LIMITED

JODHPUR-AHMEDABAD-BHIWANDI-MUNDRA
CIN:- U2424RJ2020PLC069105

July 13, 2025

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai, Maharashtra – 400 051

Script Code: DHARIWAL

Sub: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir(s)/Madam(s),

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 please find enclosed the copies of newspaper advertisement published regarding registration of E-Mail address by Shareholders, in compliance with MCA Circulars. This is for your information and records.

The Newspaper advertisement was published in following Newspapers:

1. Financial Express (English)
2. Nafa Nuksan (Hindi)

This is for your information and records.

Thanking you,

For DHARIWALCORP LIMITED

SALONI KACHHWAHA
Company Secretary and Compliance officer
M. No.: A67240

1

For Your Information

Transaction volume of cards (in billion)



Credit Cards:

FY22-23: 2.9 (+0.7)

FY21-22: 2.2

Debit Cards:

FY22-23: 3.4 (-0.5)

FY21-22: 3.9

(RBI, NPCI, PwC analysis)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत तवन



हर सुबह घर में गंध-पाठ अवश्य करें, फिर चाहे वह मोबाइल से ही क्यों न हो। उसकी दिव्य तरंगों से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा तरंगें अपना काम करेंगी।

- श्री कल्याण

Thoughts of the time

The health of nations is more important than the wealth of nations .

-Will Durant

Stop being afraid of what could go wrong and start being positive about what could go right.

-Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घणौ लोभ गल्लै वढ़ावै

अधिक लोभ गला कटवाता है

केवल लोभ की खातिर लोभ करना प्राणघातक है। अत्यधिक लोभ मनुष्य का अंत बुरा ही होता है।

-स्व. विजय दान देवा
साधार : कृपायन संस्थान, बीकानेर

एफसीआई के खज़ांची ने छह साल में 19 करोड़ रुपये का निवेश किया : सीबीआई

नयी दिल्ली@एजेंसी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पता लगाया है कि नगालैंड में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक खज़ांची ने कथित तौर पर 19 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि पिछले छह वर्षों में वेतन से उसे कुल 40 लाख रुपये मिले थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिटोका शोहे पर अप्रैल 2019 से जून 2025 के बीच कथित रूप से 18.99 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 1,797.73 प्रतिशत अधिक है।

एफसीआई के दीमापुर मंडल कार्यालय में सहायक ग्रेड-1 (लेखा) और खंजांची पद पर तैनात शोहे ने कथित तौर पर छह साल की अवधि में 39.91 लाख रुपये वेतन अर्जित किया। अब शोहे को निर्लांबित कर दिया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, शोहे ने भारतीय स्टेट बैंक से 64.9 लाख रुपये का आवास ऋण लिया था, जिसमें से 21.79 लाख रुपये उसने चुका दिए हैं। प्राथमिकी में दिए गए विवरण के अनुसार, शोहे ने अपना घर बनाने के लिए विभिन्न सामान पर लगभग 23.5 लाख रुपये खर्च किए और लगभग 93,000 रुपये के प्रीमियम के साथ एक बीमा पॉलिसी खरीदी।

इसमें कहा गया, “लेकिन उस इमारत के अंदरूनी भाग सहित निर्माण/विद्युत लागत को ध्यान में नहीं रखा गया क्योंकि अभी तक सीपीडब्ल्यूडी ने इसका मूल्यांकन नहीं किया है।”

प्राथमिकी में कहा गया है कि तलाशी के दौरान और उसके बाद एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह कहना उचित है कि एफसीआई के दीमापुर मंडल कार्यालय के खज़ांची (वर्तमान में निर्लांबित) बिटोका शोहे ने एक अप्रैल, 2019 से 14 जून, 2025 के बीच अवैध रूप से धन अर्जित किया।

अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग

जयपुर@का.सं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित निवेश एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए इन एमओयू में शामिल सौर व बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाए।

शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश समझौतों की प्रगति के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हुए एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों में से अब

सीएम ने कहा, सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाए, ‘राइजिंग राजस्थान’ एमओयू समीक्षा बैठक



तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य को साकार करने में निवेश का अहम योगदान है। राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू की नियमित समीक्षा की जाए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं पंप स्टोरेज तथा बैटरी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में 6 हजार मेगावाट आवर की

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित की जाने वाली सौर व बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए तथा इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर सहित अन्य नवाचारों को अपनाए जाने के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रेस्ड बायो गैस व बायो फ्यूल प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं शेष रहे एमओयू के श्रेणीवार विभाजन के साथ तय समय सीमा में धरातल पर लागू करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संबंधित जिला कलक्टरों वीसी के माध्यम से जुड़े।

रीको के अंतर्गत शून्य कराधान व्यवस्था लागू करने का प्रयास: राठौड़

जोधपुर@नि.सं। उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने यहां औद्योगिक विकास से जुड़े विविध पक्षों पर स्थानीय उद्यमियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को आधार बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। इस नीति के अंतर्गत संसाधनों के पुनः उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उद्योगों को पर्यावरण-संवेदनशील और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना की जाएगी, जो विश्वस्तरीय अधोसंरचना से युक्त होंगे। इन पार्कों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कर्नल राठौड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार का प्रयास है कि



सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोधपुर को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने हेतु संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में सांसद राजेन्द्र गहलोत, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राज्यसभा , प्रसन्नचन्द मेहता, मारवाड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश जीरावला, लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शंतिलाल बालड अनेक उद्यमियों ने भाग लिया।

रीको के अंतर्गत शून्य कराधान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि पूर्ण राजस्व को औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में ही पुनर्निवेशित किया जा सके। यह नीतिगत परिवर्तन राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी तथा निवेशोन्मुख बनाएगा। राठौड़ ने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु ‘सरकार – उद्योग – प्रशासन’ की त्रिस्तरीय

नेशनल • इंटरनेशनल

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.34 प्रतिशत घटकर 5.63 लाख करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली@एजेंसी

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में 10 जुलाई तक 1.34 प्रतिशत घटकर लगभग 5.63 लाख करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से अधिक ‘रिफंड’ के कारण टैक्स कलेक्शन कम हुआ है।

नेट कंपनी टैक्स कलेक्शन 3.67 प्रतिशत गिरकर लगभग दो लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 2.07 लाख करोड़ रुपये था। नॉन-कंपनी टैक्स (जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म शामिल हैं) 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा। एक अप्रैल से 10 जुलाई के बीच सिक्स्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कलेक्शन 17,874 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान देश का कुल नेट कलेक्शन 5.63 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 5.70 लाख करोड़ रुपये से 1.34 प्रतिशत



कम है। चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अब तक जारी किया गया नेट रिफंड 38 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा। एक अप्रैल से 10 जुलाई तक ग्रास कलेक्शन (रिफंड से पहले) 6.65 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.44 लाख करोड़

रुपये से 3.17 प्रतिशत अधिक है। ग्रास कंपनी टैक्स कलेक्शन 10 जून तक 9.42 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि ग्रास नॉन-कंपनी टैक्स कलेक्शन 1.28 प्रतिशत घटकर 3.57 लाख करोड़ रुपये रहा। शारदुल अमरचंद मंगलडास एंड

कंपनी की साझेदार गौरी पुरी ने कहा कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी मुख्य रूप से टैक्स रिफंड की मात्रा में वृद्धि के कारण है। पुरी ने कहा, यह करदाता को सेवाओं में सुधार पर सरकार के ध्यान को दर्शाता है। समय पर और कुशल रिटर्न कारोबारी सुगमता को बढ़ाता है। चालू वित्त वर्ष में, सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 25.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.7 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में सिक्स्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) से 78,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। सरकार ने 10 जुलाई तक डायरेक्ट टैक्स

भारत की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 3-5 वर्षों में 10-12 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी : रिपोर्ट

नई दिल्ली@आईएनएस

भारतीय लाइफ इंश्योरेंस उद्योग ने संशोधित सरेंडर वैल्यू नियमों, कम क्रेडिट लाइफ सेल्ल्स और ग्रुप सिंगल प्रीमियम के प्रभाव के बीच जून में 41,117.1 करोड़ रुपए के नए बिजनेस प्रीमियम रजिस्टर किए। यह जानकारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेंटेंस के एसोसिएट डायरेक्टर सौरभ भालेराव ने कहा, पहली तिमाही आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए एक धीमी अवधि होती है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत के बाद आती है, जब अधिकांश रिटेल कस्टमर आखिरी समय में जल्दबाजी में पॉलिसी खरीद चुके होते हैं।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में तिमाही आधार पर वृद्धि 4.3 प्रतिशत रही है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण उपभोक्ता मांग में कमी और संशोधित सरेंडर

वैल्यू दिशानिर्देशों का प्रभाव रहा। भालेराव ने कहा कि एलआईसी और निजी कंपनियों ने इंडिविजुअल सिंगल और नॉन-सिंगल प्रीमियम में प्रीमियम वृद्धि दर्ज की है, जो दर्शाता है कि उनके पास एक मजबूत वितरण चैनल है और सरेंडर वैल्यू नियमों में बदलाव के बीच वे उच्च मूल्य वाली पॉलिसियों की ओर बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत और वार्षिक समूह व्यवसाय ने इस महीने की वृद्धि को गति दी।

बैंकों द्वारा जमा राशि एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करने से एजेंसी चैनल पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना है। केयरएज रेंटेंस के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल ने कहा, इसके अलावा, प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम का उद्देश्य नई कंपनियों को बाजार में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित कर बाजार में पेनिट्रेशन बढ़ाना है।

ब्रीफ न्यूज

राजस्थान एआई पॉलिसी-2025 के प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स की परामर्श कार्यशाला

जयपुर@का.सं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस



पॉलिसी-2025 लाने जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-प्रधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास का उभरता केंद्र बनाना है। विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने कहा कि यह नीति स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शहरी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देगी, ताकि जन-केंद्रित सेवाओं में सुधार हो और आर्थिक विकास को गति मिले। अर्चना सिंह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय एआई पॉलिसी स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। दो सत्रों में आयोजित हुई इस कार्यशाला के पहले सत्र में ओरिंकल, आईबीएम, ऑर्बिट, अनैस्ट एंड थिंग, एनईसी जैसी एआई क्षेत्र की देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरे सत्र में आईआईएम उदयपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और एआई के विद्यार्थियों ने ड्राफ्ट पॉलिसी पर अपने विचार रखे। राजस्थान एआई पॉलिसी-2025: नीति के प्रमुख उद्देश्यों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, नैतिक और जिम्मेदार एआई विकास, मजबूत कानूनी ढांचे की स्थापना, कुशल कार्यबल तैयार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

चैम्पियन प्राइम सैलून एवं ग्लेन एकेडमी का उद्घाटन

उदयपुर@नि.सं। हेयरकट और स्टाइलिंग के लिए राजस्थान के नामी चैम्पियन सैलून ने उदयपुर में चैम्पियन प्राइम सैलून तैयार किया है, इसका उद्घाटन परिवार के वरिष्ठ सदस्य दुर्गेश सेन ने किया। इस अवसर पर चैम्पियन सैलून के डायरेक्टर जमनेश सेन और कमलेश सेन उपस्थित थे। कमलेश सेन ने बताया कि यह चैम्पियन का 12वां शोरूम है। लक्जरी सैलून में एक साथ 50 ग्राहकों को सर्विस दी जायेगी। यहां आने वाले ग्राहकों को 15 अगस्त तक 20 प्रतिशत फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। कमलेश सेन ने बताया कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा और लक्जरी सैलून है जहां पर ग्राहकों की सुंदरता और ग्रूमिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसे प्रीमियम बनाया गया है। इसके तहत हर सर्विसेज के लिए अलग से स्थान बनाए गए है, जैसे पॉम एंड सोल, लॉज, हैयर वॉल्ट रूम, पॉलिस एंड पॉप रूम, वेडिंग वाइप रूम, शैम्पू स्टेशन, ग्लेम एंड ग्लो एरिया, ग्रोम एंड ग्रो एरिया, हेयर स्पा रूम, कांडसलिंग रूम और किड्स सेक्शन होगा। किड्स के लिए बाइक और कार वाली चेयर होगी। इसके अलावा यहां पर टैटू आर्ट, पियर्सिंग, नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट, हेयर एक्सटेंशन, हेयर पैचिंग, डर्मा फेशियल, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल ट्रीटमेंट, एचडी मेकअप सर्विस एचडी और बच्चों के लिए विशेष सैलून सेवाएं उपलब्ध रहेगी। कमलेश सेन ने इस क्षेत्र में और विस्तार की अपेक्षा की। प्रतिशिक्षण के नजरिये से हमने ग्लेम स्कूल नामक एकेडमी भी शुरू की है।

श्रीलंका में बने गारमेंट्स को ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री प्रवेश

कोलंबो@एजेंसी। अमेरिका द्वारा श्रीलंका से आयातित सभी वस्तुओं पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने यहां विनिर्मित गारमेंट्स को शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की। इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। कोलंबो में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एंड्रयू पैट्रिक ने कहा, यह श्रीलंकाई गारमेंट्स क्षेत्र और ब्रिटेन के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ब्रिटेन सरकार ने बृहस्पतिवार को उदार मूल नियम लागू किए हैं, जिनसे विकासशील देशों को लाभ होगा। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाए जाने पर देश के सबसे बड़े उद्योग मंडल ने कहा कि उच्च शुल्क से हजारों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। उद्योग मंडल ने सरकार से बेहतर परिणाम के लिए अमेरिका के साथ आगे बातचीत जारी रखने का आग्रह किया। श्रीलंका सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह शुल्क पर 'द्विपक्षीय रूप से लाभकारी' परिणाम के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगी। शुल्क एक अगस्त से लागू होगा।



DHARIWALCORP LIMITED
36, Narayan Nagar, Shobhawato Ki Dhani, Pal Link Road, Jodhpur, Rajasthan-342001 Office No. +91 7014131630 CIN:- U24248RJ2020PLC069105
E-Mail : investor@dharivalcorporation.com, admin@dharivalcorporation.com Web : dharivalcorporation.com

5वीं वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सूचना

धारीवालकॉर्पोर लिमिटेड के सदस्यों को पौर्वाची (अग्री) वार्षिक सामान्य बैठक ("AGM") गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:30 बजे, G-764, कोलकाता इंटरनेशनल एरिया, कलकत्ता, ज़ोफपुर, राजस्थान - 342012 में MCA रजिस्टर संख्या 14/2020, 17/2020, और 20/2020 (MCA रजिस्टर) तथा SEBI रजिस्टर (पुनः कि नॉटिफ में परिभाषित किया गया है) के अनुपालन में आयोजित की जायेगी, ताकि AGM के नीति में दिए गए व्यवसायिक विषयों का निवारण किया जा सके।

MCA रजिस्टर और SEBI रजिस्टर के अनुसार, AGM का नॉटिफ और वार्षिक रिपोर्ट इंटरनैटिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी खातों की सूची में दर्ज है, 12 जुलाई, 2025 ("दिनांक निर्दिष्ट") को अंतिम है, जो डिजिटलरी से प्राप्त हुई है और किनका ईमेल पता कंपनी/डिजिटलरी प्रतिभागियों का कंपनी के रजिस्टर और स्टोकर ट्रेडिङ एंड (RTA) डिजिटलर लॉकेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत है।

एडीएस नॉटिफ कंपनी की वेबसाइट (www.dharivalcorporation.com), कंपनी के अटॉरनी की वेबसाइट (investor.bigshareonline.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

नॉटिफ प्राप्त करने हेतु ईमेल पते पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया :

(i) नौकित रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपने पंजीकृत कर्मों लिखे हुए दस्तावेज़ित फार्मन पर की स्कैन फोटो, पूर्ण पता, पंजीकृत करवाने हेतु ईमेल पता एवं पंजीकृत पते के संबंध में वेन कर्ड और अन्य दस्तावेज़ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट, आवात कर्डी) को स्व अभिगम्यता फॉर्म, एम्बेड ईमेल पते investor@dharivalcorporation.com अथवा अटॉरनी के ईमेल पते investor@bigshareonline.com पर भेजे।

(ii) शेयर ईमेल रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपने ईमेल पते, अपने डिजिटलरी प्रतिभागियों के माध्यम से पंजीकृत करवाएं।

सदस्य से अनुरोध है की कृपया एडीएस नॉटिफ में वर्णित दिवसियों, एवं विशेष रूप से एडीएस से पहले रिमोट ई-नॉटिफ एवं एडीएस के दौरान ई-नॉटिफ से संबंधित दिवसियों, ध्यानपूर्वक पढ़ें।

इन संबंध में सभी तंत्र / प्रश्न हमारे ईमेल पते investor@dharivalcorporation.com पर संबोधित किए जाने चाहिए।

अग्रतः जानकारी, एक्ससेस एरिया के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और स्वयं के लिए दी जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से धारीवालकॉर्पोर लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित -

सहनीनी कपूर/का

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या : A67240

दिनांक : 12 जुलाई, 2025

स्थान : जयपुर




CMYK